



13-8-84

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 1984/आषाढ़ 15, 1906

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 1984/ASADHA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली 6 जुलाई, 1984

का० आ० 489 (अ) - भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 387 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1979, का० आ० 497 (अ) तारीख 5 जुलाई, 1980, का० आ० 541 (अ) तारीख 6 जुलाई, 1981, का० आ० 480 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1982 और सं० का० आ० 497 (अ) तारीख 7 जुलाई, 1983 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 426 (अ) तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नामक औद्योगिक उपक्रम के रखरखाविक एकक का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की

उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 7 जुलाई, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है के लिए ग्रहण कर लिया गया था और मैसर्स असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध मैसर्स असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के पास 31 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए बना रहे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 दिसम्बर, 1984 तक को जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रभावी बना रहेगा।

[सं० 4(4)/80-सी यू एस]

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

## ORDERS

New Delhi, the 6th July, 1984

S.O. 489(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E), dated the 8th July, 1974 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), Nos. S.O. 387(E), dated the 7th July, 1979, S.O. 497(E), dated the 31st July, 1980, S.O. 541(E), dated the 6th July, 1981, S.O. 480(E), dated the 7th July, 1982 and S.O. 497(E), dated the 7th July, 1983, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) upto and inclusive of the 7th July, 1984, and Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue to be under the management of Messrs Assam Industrial Development Corporation Limited upto and inclusive of 31st December, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect upto and inclusive of the 31st December, 1984.

[No. 4(4)/80-CUS]

का० आ० 490 (अ).—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 136(अ) तारीख 8 जुलाई, 1974 द्वारा मैसर्स एसोसिएटेड इन्डस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर नाम के औद्योगिक उपक्रम के (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) रसायनिक एकक का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 7 जुलाई, 1979 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था;

और उक्त आदेश की अवधि को 31 दिसम्बर 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रसायन उद्योग में उत्पादन को मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18 कक की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरणपत्रों, करारों, परिनिधोरणों, पंचातों स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जो उनमें भिन्न है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित है) जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कंपनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, प्रवर्तित 31 दिसम्बर, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए निरन्वित रहेगा और उक्त तारीख से पहले उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निरन्वित रहेंगे।

[फा० सं० 4(4)/80सीयूएस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

S.O. 490(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 426(E), dated the 8th July, 1974, the management of the chemical unit of the industrial undertaking known as Messrs Associated Industries (Assam) Limited, Chandrapur (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period upto and inclusive of the 7th July, 1979;

And whereas, the duration of the said Order has been extended from time to time up to and inclusive of the 31st December, 1984;

And whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the chemical industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with clause (b) of the proviso to sub-section (2) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking

or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period upto and inclusive of 31st December, 1984 and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. 4(4)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

